NERP-2016-1

ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक: प.3(2)(1)रोल / निर्वा / 2015 / पार्ट–II / NERP / 942 **जयपुर, दिनांक** 03-03-2016

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान–2016 मतदाता सूचियों को साफ–सुथरा एवं त्रुटिरहित बनाने तथा मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थीकरण (Rationalization) के संबंध में।

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 23 / 2016–ईआरएस दिनांक 27.02.2016 एवं इस विभाग का पत्र क्रमांक 830 दिनांक 24 फरवरी, 2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 27.02.2016 (प्रति संलग्न) द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों को साफ सुथरा एवं त्रुटिरहित बनाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए है। इसके साथ–साथ आई.टी. तकनीक का प्रयोग करते हुए मतदाता सूचियों में विभिन्न त्रुटियों को चिन्हित कर प्रपत्र 1–8 में सांख्यिकी सूचना का संकलन कर इसका विश्लेषण करने के बाद मतदाता सूचियों की हैल्थ हेतु निर्धारित विभिन्न मापदण्डों में पाए गए अन्तर (gaps) को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार लाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए है।

2. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूर्व में "मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु आयोजित राष्ट्रीय अभियान 2015" की निरन्तरता में संदर्भ तिथि 01.01.2016 के बाद मतदाता सूचियों के दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अन्तिम प्रकाशन के बाद निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया में "**मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान 2016**" 1 मार्च, 2016 से प्रारम्भ करने के निर्देश दिए है। इसके साथ–साथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित

मतदान केन्द्रों की सीमाओं एवं लोकेशन को ध्यान में रखते हुए इनके सुव्यवस्थीकरण (Rationalization) करने के निर्देश भी दिए है।

3. मतदाता सूचियों को साफ–सुथरा एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से माह मार्च में प्रारम्भिक तैयारियों के रूप में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है।

3.1 संदर्भ तिथि 01.01.2016 के संदर्भ में मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 11 जनवरी, 2016 को किया गया है। अन्तिम प्रकाशन से पूर्व राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 1–8 में विधानसभा क्षेत्रवार आंकडों का संकलन कर विभाग स्तर से रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित की गई थी। आयोग स्तर पर उक्त प्रपत्रों में सभी जिलों द्वारा प्रस्तुत सूचना का विश्लेषण किया गया तथा मतदाता सूची के विभिन्न मापदंडों यथा मतदाता जनसंख्या अनुपात, लिंगानुपात, विभिन्न आयु वर्गो के मतदाताओं के पंजीयन की स्थिति, 18–19 वर्ष की आयु वर्ग में पंजीकरण की स्थिति का विश्लेषण कर राज्य के विभिन्न जिले जिनमें अन्तर पाया गया है, को चिन्हित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। तद्नुसार विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 830 दिनांक 24.02.2016 से आपको आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किए गए है।

3.2 इसके साथ–साथ आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची में शत–प्रतिशत मतदाता की फोटों मुद्रित होना, शत–प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करना, मतदाता सूची में पंजीकृत ऐसे मतदाता जिनमें एक से अधिक मतदाताओं को एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है अथवा ऐसे मतदाता जिनकी मतदाता सूची में फोटों स्पष्ट रूप से मुद्रित नहीं है को मतदाता सूची के डेटाबेस सॉफ्टवेयर के आधार पर त्रुटियों को चिन्हित कर, फील्ड में इनका सत्यापन कर ठीक करवाया जाना है। मतदाता सूचियों से मृत, स्थानांतरित एवं दोहरी प्रविष्टियों को हटाने तथा मतदाता सूची में मतदाताओं से संबंधित अन्य जानकारी यथा मोबाईल नम्बर आदि उपलब्ध कराने के विषय में इस राष्ट्रीय अभियान के दौरान कार्य करने के निर्देश दिए गए है।

3.3 जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) से अनुरोध है कि आयोग द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2016 से प्रारंभ किये गये इस राष्ट्रीय अभियान के दौरान विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 830 दिनांक 24 फरवरी, 2016 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने स्तर पर विधानसभा क्षेत्रवार मतदाता सूचियों के ऑकड़ों का विश्लेषण करें तथा मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न मापदंडों जिनका विधानसभा क्षेत्रवार अन्तर दृष्टिगत हो रहा है चिन्हित करें। इसी प्रकार की कार्यवाही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा की जाएगी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने स्तर पर विधानसभा क्षेत्रों की सांख्यिकी सूचना का मतदान केन्द्र स्तर तक विश्लेषण कर विभिन्न पैरामीटर्स के क्रम में जो अन्तर दृष्टिगत हो रहा है को चिन्हित करेंगे। उक्त कार्यवाही करते समय पूर्व के वर्षो के ऑकड़ों को भी अपने साथ रखेंगे। वर्तमान में सभी विश्लेषण वर्ष 2011 की जनसंख्या को वर्ष 2016 के अनुसार प्रोजेक्टेट करते हुए की जाएगी। **यह कार्यवाही आवश्यक रूप से 15 मार्च, 2016 तक पूर्ण कर ली जाये। इस विश्लेषण के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले से इस बीच एक विश्लेषणात्मक नोट में कार्य योजना दिनांक 18 मार्च, 2016 तक विभाग को प्रेषित करेंगे ताकि राज्य के परिपेक्ष्य में नोट दिनांक 25 मार्च, 2016 तक आयोग को प्रेषित किया जा सके।**

3.3 जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूचियों के विभिन्न पैरामीटर्स में चिन्हित किए गए गैप के निस्तारण के विषय में स्वीप कार्ययोजना तैयार करेंगे जिससे कि विभिन्न वर्गो में चिन्हित किए गए अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए आगामी माहों में कार्यवाही की जा सके। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त समस्त कार्यवाही माह मार्च 2016 में की जानी है। **इसके पश्चात् आगामी माहों में बीएलओ/सुपरवाईजर के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी। जिसके विषय में दिशा-निर्देश यथा समय प्रेषित कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय अभियान के दौरान समस्त कार्यवाही आगामी 31 अगस्त, 2016 तक पूर्ण की जानी है।**

4. मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु चलाये गये उक्त राष्ट्रीय अभियान के दौरान मतदाता सूचियों में दोहरी प्रविष्टियों एवं अन्य त्रुटियों को हटाया जाना है। मतदाता सूचियों के डेटाबेस के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2016 से पूर्व चिन्हित की गई विभिन्न त्रुटियों की सूची बीएलओ के माध्यम से सत्यापित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित की गई थी। समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) द्वारा हाल ही में सम्पन्न पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अथवा इससे पूर्व निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान चिन्हित की गई इन सभी त्रुटियों को ठीक करते हुए दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में इन्हें ठीक कर लिया गया होगा। **जिला निर्वाचन अधिकारी कृपया निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास उपलब्ध उक्त सूचियों के अनुसार यह सुनिश्चित कर लें कि सभी त्रुटियों /दोहरी प्रविष्टियों अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में ठीक कर लिया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो इन सूचियों का प्रयोग वर्तमान राष्ट्रीय अभियान के दौरान किया जाकर कार्यवाही की जाए।**

4.1 विभाग द्वारा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर चिन्हित की गई दोहरी प्रविष्टियों यथा एक से अधिक मतदाता को एक ही नम्बर का फोटो पहचान पत्र जारी किया जाना या एक मतदाता को एक ही मतदाता फोटों पहचान पत्र एक से अधिक बार जारी किया जाना आदि दोहरी प्रविष्टियों की सूची प्रेषित की गई थी। इस विषय में भी समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान कार्यवाही करते हुए उन्हें ठीक किया जाकर दिनांक 11 जनवरी, 2016 को तद्नुसार मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। यदि तत्समय उक्त कार्यवाही नहीं की गई है तो इस कार्य को भी आगामी राष्ट्रीय अभियान के दौरान किया जाये। इस विषय में विस्तृत दिशा–निर्देश आपको तत्समय दिए गए है।

4.2 भारत निर्वाचन आयोग ने इस राष्ट्रीय अभियान के दौरान मतदाता सूचियों में मृत मतदाताओं के नाम विहित प्रक्रिया के अनुसार विलोपित करने के निर्देश दिए है। इस विषय में आपका ध्यान विभाग के पत्र क्रमांक 4717 दिनांक 11.12.2015 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों

में कार्यरत पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु कार्यालयों द्वारा मृत/जन्म की सूचना **''पहचान पोर्टल''** पर उपलब्ध है (जिसका लिंक विभाग के वेबसाईट पर दिया गया है), से सूचना प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करें। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से अनुरोध है कि **''पहचान पोर्टल''** पर अपने क्षेत्र से संबंधित मृत्त मतदाताओं की सूची प्राप्त कर लें तथा आगामी राष्ट्रीय अभियान के दौरान बीएलओ के माध्यम से इसे सत्यापित करवाकर मृत मतदाताओं के नाम विहित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता सूची से विलोपित करने की कार्यवाही की जाए।

4.3 **आयोग में निर्देशानुसार इस राष्ट्रीय अभियान के दौरान ऐसे पात्र व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में अभी तक पंजीकृत नहीं है विशेषकर 18–19 आयु वर्ग के ऐसे युवा जिनके नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो पाए है, उनसे प्ररूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएगे तथा मतदाता सूची में यदि गलत नाम दर्ज है तो विलोपन हेतु प्ररूप 7 में आवेदन प्राप्त किए जाएगे। इस प्रकार से मतदाता सूची की प्रविष्टि में संशोधन हेतु प्ररूप 8 में आवेदन पत्र प्राप्त किए जाए।** उक्त कार्यवाही बी.एल.ओ. द्वारा घर–घर जाकर अथवा मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर, की जायेगी। इस हेतु पृथक से कार्यक्रम निर्धारित की आपको अवगत कराया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि इस अभियान हेतु आवश्यक प्रपत्र पूर्व की भांति जिला स्तर पर ही मुद्रित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5. अभियान के दौरान प्ररूप 6, 6ए, 7, 8 एवं 8ए के आवेदन प्राप्त होगें उनका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण किया जाएगा तथा तद्नुसार निरन्तर अद्यतन की प्रकिया के दौरान तैयार की जाने वाली पूरक सूची 7 विभाग के पत्र क्रमांक 674 दिनांक 11 फरवरी, 2016 में दिए गए निर्देशों के अनुसार तैयार की जाएगी।

6. **मॉनीटरिंग** – आयोग द्वारा इस कार्यक्रम की दिन प्रतिदिन मोनीटरिंग डैश बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। आयोग द्वारा आयोग के वैब पोर्टल पर उक्त व्यवस्था यथाशीघ्र उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से अनुरोध है कि वह दिन–प्रतिदिन डैशबोर्ड पर सूचना आदिनांक रखें। इस कार्य की मोनीटंरिग हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) से

यह भी अनुरोध है कि वह जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें, जो कि इस अभियान से संबंधित सभी प्रारम्भिक कार्यवाही करते हुए आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे जिससे कि बीएलओ द्वारा घर–घर सत्यापन की अवधि के दौरान प्रभावी रूप से कार्यवाही की जा सके।

7. **अभियान का प्रचार–प्रसार** – भारत निर्वाचन आयोग ने इस अभियान के प्रचार प्रसार के विषय में दिशा–निर्देश दिए है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अपने स्तर पर प्रपत्र 1–8 में सूचना का सकंलन करने के पश्चात् विभिन्न चिन्हित किए गए गैप को टारगेट ग्रुप्स चिन्हित कर तद्नुसार स्वीप कार्ययोजना तैयार करें तथा तद्नुसार प्रचार प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस कार्यक्रम के दौरान जिले में आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों के विषय में समय–समय पर प्रेस नोट जारी कर प्रचार प्रसार किया जाए। इस कार्यक्रम की जानकारी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दी जाए जिससे कि उनके द्वारा मतदान केन्द्रों के लिए नियुक्त बीएलए का सहयोग प्राप्त किया जा सकें।

8. **प्रशिक्षण** – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **''मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान 2016''** के अन्तर्गत विशेषकर इस कार्य से जुड़े बीएलओ, सुपरवाईजर, ईआरओ एवं एईआरओ आदि को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए है। प्रशिक्षण के विषय में विस्तृत दिशा–निर्देश यथाशीघ्र आपको प्रेषित किए जाएगे।

9. **मतदान केन्द्रों का सुव्यवस्थीकरण (Rationalization)** – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस अभियान के दौरान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आयोग द्वारा अधिसूचित मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करने के दिशा–निर्देश भी दिए है। जैसा कि आपको विदित है कि गत् विधानसभा/लोकसभा आम चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया गया है। आयोग ने मतदान केन्द्रों के प्रस्तावित सुव्यवस्थीकरण (Rationalization) की कार्यवाही के दौरान सभी मतदान केन्द्रों का शत–प्रतिशत भोतिक सत्यापन कर इसकी सीमाओं/लोकेशन को दृष्टिगत रखते हुए इसको सुव्यवस्थीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही माह मार्च, 2016 में ही प्रारम्भ की जानी है जिसके विषय में दिशा–निर्देश यथाशीघ्र विभाग द्वारा जारी किए जा रहें है।

10. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) कृपया माह मार्च में उपरोक्तानुसार प्रारंभिक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें ताकि 01 अप्रैल, 2016 से फील्ड में गतिविधियॉ प्रारम्भ की जाकर आयोग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय अभियान के दौरान 31 अगस्त, 2016 तक सभी कार्य सम्पादित किए जा सके।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(राजेश यादव)
कार्यवाहक
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

कमांक:प3(2)(1)रोल / निर्वा / 2015 / पार्ट–II / NERP / **जयपुर, दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
2. समस्त संभागीय आयुक्त, (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
3. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
4. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (आई.टी.) कृपया उक्त दिशा–निर्देश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
5. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

No. 23/2016-ERS

Dated: 27th February 2016

To,

The Chief Electoral Officers of All States/UTs
(Except Assam, Bihar, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu, Telangana and West Bengal)

Subject: National Electoral Rolls Purification (NERP) 2016 drive to improve the health of the Electoral Rolls (ERs) and to rationalize the Polling Stations (PSs) boundaries and location - regarding.

Sir/Madam,

The purity of an electoral process is directly dependent on the health of the electoral rolls. It has been the Commission's constant endeavour to improve the fidelity of Electoral Rolls by focused efforts to improve the enrolment and remove multiple entries & data errors by effective use of technology and requisite facilitations and laid down procedures. These activities related to ER Purification coupled with the effective SVEEP strategies will educate and motivate voters to volunteer to get their multiple entries removed, get the errors and addresses corrected and updated. The Commission also decided to address the polling station related issues such as rationalization in a holistic and comprehensive way.

2. In just concluded SR 2016 many gaps identified and communicated to CEOs and to DEOs through CEO. These gaps also need to be closed to the extent possible.

3. With a view to achieving the above objective, the Commission has decided to launch an intensive drive **"National Electoral Rolls Purification (NERP) 2016** which will include enrolment of all eligible citizens and removal of repeated and multiple entries; entries of dead, shifted & absent voters, correction of errors in EPIC and removal of other data errors. During this drive repeat images will also be corrected, missing photographs will be collected; poor quality of images will be replaced by a good quality photographs. The gaps of SR 2016 will be closed to the extent possible.

4. The Commission has further decided to standardize and rationalize the sections with in a part, Part/PS boundaries and Polling station locations keeping in view the voters' convenience and facilities available along with the ease of conduct of poll, with due consultation with stakeholders' including public and political parties. In this process, (i) mapping of the Basic Minimum Facilities (BMFs) for voter's facilitation and convenience , (ii) preparation of improved rough sketch Maps (Nazari Naksha) using IT techniques like CAD

and GIS Maps, (iii) PS images, (iv) key map for reaching the PS and CAD drawing with model lay out on poll day should be done for each PS.

5. **NERP 2016 drive is to be launched on 1st March, 2016 and to be completed on or before 31st August, 2016. Month of March will be used as a preparatory phase and actual work will commence from 1st April, 2016.**

6. The Commission has directed that the Census 2011 databases projected to 2016 should be used as a benchmark to compare and analyse the critical gaps in the ERs with respect to the age Cohort, Elector/Population ratio and Gender ratio. Higher youth registration (18-19 years' age group) and 100% EPIC/PER are to be kept as the main focus areas.

7. Your attention is invited to the Commission's letter No. 23/2016-ERS, dated 3rd February 2016, and the Video Conference discussion with the Chief Electoral Officers on 5th February 2016. Broad guidelines to implement NERP 2016 are follows:

7.1 AIMS AND OBJECTIVES

(a) **Electoral Roll related Activities**

1- Removal of gaps in E/P ratio and gender ratio with focus on maximization of enrolment in 18-19 age groups.
2- Ensuring 100% coverage of EPIC/PER.
3- Ensuring good quality photographs, if necessary, by replacing blurred, poor quality and repeat and non human images,
4- Identification and corrections of various types of inaccuracies/errors in electoral rolls using IT tools and then making necessary correction in Electoral database.
5- Removing from the electoral rolls any dead/shifted/multiple entries, gainfully using IT applications.
6- Collection of contact details of electors and/ or their family members. (It is option of the elector to disclose. If disclosed, he would get many Election related services. The data, under no circumstance to be put in public domain or shared with any person or authority)
7- Updation of control tables of ER database.

(b) **Polling station related Activities**

1- Standardization of sections and modification of the part boundaries of existing polling stations to make a polling station compact in perspective of polling area with voters strength of about 1200 in rural area and about 1400 in urban area,

3- To ensure that voters are not required to travel long distances (over 2KM) and/or cross geographical barriers like river, ravines, rivulets, spills, deep forest etc. to reach PS.

4- To identify and map alternative locations within the polling areas with BMFs etc.

5- To make Rough Sketch Maps (*Nazri Naksha*) as a precise PS Map drawn using CAD with correct dimensions and model layout, with BMF information, actual images of PS, Google- Map & street view and Key map on how to reach, wherever felt necessary.

7.2 Electoral Roll Component of NERP 2016 Drive

(A) STRATEGIES

(a) Identification of the Gaps and finalising the strategy and time line

i. CEO/DEOs/EROs shall do statistical analysis of data of Format 1-8 in respect of finally published electoral rolls with reference to 01.01.2016 as the qualifying date in order to find out major gaps in terms of E/P ratio, gender ratio, age co-hart imbalances, particularly of 18-19 years age group, abnormal increase or decrease in number of voters in any area, <100% PER/EPIC in ACs/ PSs and service electors. No need to emphasize that the analysis should be done with due care and promptitude. For a better analysis, previous years' data should also be taken into consideration for better appreciation of the scenario by comparing using charts etc. If analysis is done at micro level i.e. polling station level, the gaps may clearly manifest which hide at macro level i.e. State/District or AC level. Since census data of 2011 including population age details is already available, the population projection to 2016 should be done on 2011.

ii. The above said analysis of data should be done by the EROs & AEROs who after discussions with BLOs & Supervisors should give analytical note to DEO concerned who shall discuss with EROs& AEROs of electoral data in respect of all ACs under their jurisdiction. After critical gaps are determined, then please check, if any cogent and logical reasons like migration due to socio economic or natural calamities etc. and/or cropping up of new colonies/habitats are there to answer the gaps. If so mention it in the note. The EROs should forward their notes to DEO concerned who shall , after discussing the same with EROs and any other concerned authorities, forward a composite analytical note to CEO along with strategies to address the issues. Finally, the CEO shall, having reviewed and analyzed district wise reports, to

prepare State analytical note and chalk out necessary strategies to address the gaps that need to be filled up. The gaps should be described in quantitative terms.

iii. Chalking out suitable strategies to address the critical gaps by sustained efforts by field election machinery good training and publicity materials should be prepared under SVEEP and properly disseminated.

iv. The Commission desires that the above activity should be completed by 25th March and an AC wise action plan of the state with identified gaps, strategy and time line etc. after completing following three stages should be sent to ECI by this.

- Analysis by EROs & AEROs (with Format 1 to 8) along with BLOs (with BLO register) & Supervisors.
- Analysis and review by DEOs along with EROS & AEROs
- Review by CEO with DEOs

v. After this is done, a fortnightly action plan of activities to bridge the identified gaps with suitable strategies within a fixed time line should be prepared and forwarded to ECI. By 31st August 2016, the aims and targets in this regard have to be achieved.

vi. A proper assessment of resources needed for the purpose should also be done.

vii. Training component is a critical part so CEO, in consultation with ECI training division chalk out a plan for it

(b) <u>Purification of Electoral Rolls</u>

The Commission appreciate that a lot of work has been done to correct the ER errors and removal of repeat/multiple entries during previous continuous updating and the last revision of electoral rolls in the States/UTs based on voluntary disclosure, de-duplication software's reports for **House to House** visit and field verification by BLOs. However, some work in this regard is still unfinished. The Commission, has therefore, decided to continue the process of error correction and repeat/ multiple entries removal following due procedure under the law in NERP 2016 drive during ongoing continuous updating of electoral rolls so as to achieve error free electoral rolls. The strategy and time lines should be stated in the action plan being sent March, 2016.

(1) Addressing the errors in ERs: Please identify the entries with probable errors of the 17 types mentioned below by running EDS (Error Detecting Software) on the ER data base centrally at CEOs level.

i. Voter first/last name is Null/Junk Characters
ii. Part No. is Null/Junk Characters

iv. Section No. is Null/Junk Characters
v. House No. is Null/Junk Characters
vi. Voter relationship #M,F,H,O or m,f,h,o/Junk Characters
vii. Voter Sex M,F,TG(Third Gender)/Junk Characters
viii. Voter gender is male but relationship is H/Junk Characters
ix. Voter relatives name is blank/Junk Characters
x. EPIC no. is less than 10/Junk Characters
xi. Age is less than 18 or greater than 100/Junk Characters
xii. Photograph exists but ID Card No. is not available
xiii. ID Card No. exists but Photograph is not available
xiv. List of Records where EPIC no. is repeating
xv. Voter gender is female but relationship is F/O for voter age > 30
xvi. Voter Status type #N,E,S,M,R or n,e,s,m,r /Junk Characters
xvii. Number of sections having no voters

(2) **Identification of multiple/repeat entries/multiple EPIC numbers**

i. The software to detect possible multiple/repeat entries should be run on the ER data base centrally at CEO level to (a) Within parts, (b) Across parts in an AC, (c) Across ACs in a district, (d) Across districts in a state. The IT division of ECI is, concurrently, making/has made National Register of Errors, and it would be made available to CEO. IT division is issuing instructions in this regard

ii. Also, using appropriate software, cases of repeated EPIC numbers and repeated images should be culled out. The IT division of ECI is also, concurrently, doing the similar exercise on National database and would share its results with CEOs soon.

iii. This has to be followed by necessary field verification, wherever needed, for corrective actions.

It is pointed out that

i. Cases where same EPIC number is allotted to more than one electors- In this case, after ERO satisfies himself that such persons are different and residing at different places, then the elector who was issued EPIC first will retain his EPIC and the other elector/s who got EPIC later on with same EPIC number, shall be issued, EPIC with new EPIC number, free of cost, after taking back old EPICs which should be disposed of by cutting into pieces after keeping a proper record.

ii. Cases of different EPIC numbers but images are same- In such cases proper verification must be done by BLOs, if the entries pertain to same person. In that case, it should be treated as a case of multiple entries and accordingly be disposed of. If it is found that they are different persons, then the incorrect image should be replaced after obtaining Form 8 with correct photograph from the concerned elector/s. New

EPICs, wherever necessary, should be issued free of cost, after taking back old EPICs which should be disposed of by cutting into pieces after keeping a proper record.

iii. The IT division of ECI will issue SOP for preparation of EPICs so as to eliminate any chance of repeated EPIC numbers or repeated images in different EPICs. Image quality parameters are being defined and would be intimated to you soon.

(3) Dead Voters: The death records of past 5 years should be obtained from the concerned authorities that are authorized under state law to maintain such records. Thorough verification in concerned parts(s) should be made to identify any possible entry of the dead voters in the rolls, and If found so, then the entry should be flagged in the concerned part /BLOs register for further field verification by the BLO.

(C)Verification

1. The aforesaid lists would need to be verified by BLOs/other field functionaries by house to house verification (H2HV) during a specific period in one go, to be decided by the CEO keeping in view various factors in mind. The BLO should visit the household with BLO register/roll and the lists to be verified. It is suggested that if possible, the H2HV of lists should be done on a specific common date in entire state duly publicized to eliminate chance of the elector sneaking to other place, after verification at one place is over, so as to present at the other place too. If needed it can be repeated on any other date also.

2. The BLOs/other field functionaries should also collect, during their H2HV of contact details of electors and/ or their family members like Mobile No. and Type (Smart phone/ Text Based),Whether Primary and /or alternate, Land line No. and E-mail address and Parents EPIC details. It is made amply clear that furnishing of these information is purely voluntary and since it is exclusively personal, in no way and under no circumstance it shall be displayed in public domain in any manner either electronically or otherwise and it shall be personal responsibility of concerned CEO/DEO.

(D)Actions by EROs

After the lists of errors/shifted/dead/multiple entries etc. are got verified, the EROs concerned shall ensure that all Forms for inclusion and transposition in form 6,6A,& 8A, deletion through form-7 or 8 for correction in entries received from citizens are disposed of and Suo moto actions, wherever required, are taken strictly following statutory provisions read with ECI guidelines. Wherever possible Form 7,8 or 8A should be obtained.

The BLO is a verifying official and the power to accept/reject an application in Form 6,6A,7 or 8 , lies with ERO/AERO only who has to pass appropriate order in each individual case , after satisfying himself.

ECI instructions on data security have to be observed strictly. In case it is found that the ERO has shared digital signature to vendor or any other person, he would expose himself for strict disciplinary action by ECI.

(E) Monitoring-

CEO is to keep a close watch on the progress of NERP 2016. Necessary super checks should be done as per ECI guidelines. It shall be the personal responsibility of DEOs to ensure that prescribed information is uploaded daily in the dashboard created for Special ER purification drive on ECI web site and to read the comments/ directions of the Commission for immediate action and compliance.

(F) Publicity and related issues

1- A comprehensive publicity campaign through all types of mass communication shall be organized to motivate the voters to voluntarily come forward to disclose any repeat/ multiple entries in ERs and repeat EPIC no. and to the relatives and neighbours of dead persons to apply for the deletion of such entries from ERs.

2- Meeting with recognized political parties at state /district level should be held during the drive inviting their specific complaints which will be verified in a time bound manner. Further, the political parties should be requested to appoint Booth Level Agents (BLAs) for all polling stations and to assist the Booth Level Officers (BLOs) during special ER purification drive in identification of repeat/ multiple entries or dead electors.

3- BLAs of the recognized political parties may be intimated through political parties that they can see that list with the BLO. An one day meeting of BLOs and BLAs should be held for exchange of relevant information.

4- The Polling station wise lists of repeated/ multiple entries, repeat EPIC nos. and dead voters shall be read over in the meeting of the concerned Wards or RWAs or the Gram Panchayat / Urban local body unit in presence of members of BAGs on a prefixed date. A proper record /minutes of such meetings should be kept and necessary action should be taken by the EROs to redress the issues.

5- A copy of the lists of probable repeat/ multiple entries, repeat EPIC nos. and

of CEO and DEOs and the URL/ web link to be informed in writing to the political parties and their valuable inputs to be invited. A media briefing will also be done at the State and District levels in this respect.

(G) Complaint Redressal

A robust mechanism for complaint redressal should be set up using suitable IT technologies. If any complaint from political parties or any other stake holders is received then after taking necessary action, a suitable reply must be given to them and a proper record of the complaints received and reply given should be maintained.

(H) Training

Special training shall be imparted to all electoral officers down to BLO level by the respective CEOs. The CEOs shall prepare and distribute a booklet on special ER purification drive to all officials and develop effective publicity material for all stakeholders. Training of IT applications shall also be arranged by CEO at State HQs. Director (IT) /(Trg) of ECI may be kept in loop in this regard.

8. Special drive for rationalization of Polling Stations:

The Commission has observed that frequent changes in location of the polling stations or its (part) boundary should be avoided. Hence, in partial modification of its existing policy to have polling stations rationalized every year, it has been decided that thorough review of the list of polling stations or rationalization of polling stations should be done either in election year or one year prior to that. Hence, there is a need to relook the list of existing polling stations so that it caters to the needs of next few years.

In case of increase in electors beyond the permissible limit, auxiliary polling stations may be set up. To address the issue of development of new colonies, and deterioration in condition of existing building availability of suitable new buildings, status of BMF, change in geographical location etc., if absolutely essential, the CEO may send proposals accordingly to the ECI for approval.

Hence all CEOs may during the NERP-16 undertake the following -

1) Providing a polling station to new colonies that have cropped up during intervening time.
2) Converting the auxiliary polling stations into main polling station. This may need re-distribution of electors between them.
3) Section rationalisation and re-assigning of electors from one polling station to other polling station, if needed to make the polling area of the polling station compact. There should not

4) To carry out physical verification of existing and probable polling stations and also check the status of BMFs.
5) The rationalization should be done after 100% physical verification of the existing and probable polling station locations and the relevant parts of the electoral rolls.

While undertaking 100% physical verification, all existing polling stations must be inspected as per existing guidelines which include the following

- Whether polling station area has been correctly and fully described in the existing polling station list.
- Whether polling station is situated outside the polling area;
- Whether voters have to cross river/canals/ravines etc. to reach the polling station;
- Whether voters are required to cover distance of more than 2 KMs to reach polling station;
- Whether the polling station location has more than 2 polling stations in rural areas or more than 4 polling stations in urban areas;
- Whether the building is dilapidated or dangerous;
- Whether the minimum area of polling station room is 20 sq meters and whether it is having two doors;
- Whether polling station is on 1st floor or above;
- Whether polling station is located in a police station/hospital/ Dhramshala/temple or a religious place;
- Whether office of any political party is situated within 200 meters from polling station location;
- Whether the building has an electric connection;
- Whether ramps have been provided for physically challenged persons;
- Whether toilet and drinking water facilities exist in the polling station premises;
- Whether there is a shed to shelter the voters from sun and rain;
- Whether the polling station has telephone connection. If yes what is the phone number;
- Whether in localities predominately inhabited by minorities, weaker sections of society like scheduled caste/tribes, the polling stations are located in such a manner that such communities are not prevented from reaching the polling station and casting their votes.

Following criteria may be kept in mind while preparing proposals for creation of new polling station after physical verification as aforesaid of polling stations: -

- Optimum number of the electors that can be assigned to a polling station is 1200 in case of rural and 1400 in case of urban areas.
- All existing auxiliary polling stations should be converted into main polling stations by dividing the electoral part.
- New polling station may be proposed if a village has more than 300 electors and a suitable Government building is available for the polling station. (This needs reconsideration by ECI)
- If a new colony with a number of dwelling units has cropped up, then new polling station may be created. The electors assigned to a neighbouring polling station should be compact.
- New / separate polling station may be created in localities predominately inhabited by minorities / weaker sections of society like scheduled caste / scheduled tribes irrespective of number of electors. (The nodal officer should give a written report prepared on the basis of inputs obtained from NGOs / civil society organizations working for the welfare of such people).
- After the rationalization of polling stations is done in this manner last minute changes in the location of polling stations should not be necessary.
- Safety of polling teams and police force sent to conduct elections should also be kept in mind while proposing polling stations in Maoist or terrorist affected areas. As far as possible in these areas, polling station should be made in places which have easy and safe access. It may also be useful if polling stations are provided in a cluster in such areas to maximize and synergize the available force.
- To make Rough Sketch Maps (*Nazri Naksha)* as a precise PS Map drawn using CAD with correct dimensions and model layout, with BMF information, actual images of PS, Google- Map & street view and Key map on how to reach, wherever felt necessary.

The entire exercise has to be done within a fixed time frame as per schedule annexed in a professional manner without fear or favour, strictly in the light of statutory provisions and guidelines of Election Commission. The idea is that before next revision thoroughly revised /updated list of polling stations is prepared and got approved by the ECI u/s 25 of the RPA 1951. Please undertake the exercise in such a professional and scientific way that after the rationalization of polling stations is done, last minute changes in the location of polling stations ...

A note on use of GIS application for PS/part boundary rationalization and search of alternative buildings with better BMFs is being finalized by IT division and would soon be sent.

Kindly acknowledge the receipt of the letter by sending an email to electoral.rolls.eci@gmail.com

Yours faithfully,

(R.K.Srivastava)
Principal Secretary

Annexure

Rationalization of polling stations-List of activities

SN	Activity to be carried out	Number of days required
1	Designating a senior officer as Nodal office for the work of physical verification of existing and probable polling stations	2
2	Detailed physical verification to verify BMF facilities and other aspects as mentioned in the letter	30
3	Preparation of preliminary proposal by RO and submission to DEO	3
4	Preparation & publication of Draft list of Polling Stations.	3
5	Control Table Entry to be done in the Election Commission of India's website	14
6	Supplying copies of the proposals of modification in the existing list of PSs to local branches of all recognized political parties.	2
7	Putting the draft list of polling stations on public domain and inviting suggestions from public	7
8	Taking decisions on suggestions made by public	5
9	Holding meeting with the political party representatives and MLAs/MPs to discuss the draft list of PSs. Suggestions received are to be taken in to consideration during such meeting.	7
10	Taking decision on suggestions made by the political party representatives and MLAs/MPs; after physical verification of the suggested locations.	10
11	Preparation of AC wise proposals (with medications, if any, suggested by political parties), scrutiny and forwarding by DEO, and submission thereof to the CEO along with the scrutiny sheet and the prescribed certificates.	21
12	Preliminary scrutiny and checking by the office of the CEO.	30
13	After thorough scrutiny, submission of proposal with comments/recommendation to the ECI for approval.	15
14	ECI's approval to the proposals submitted by the office of CEO, at least one month before the date of Draft Publication of the Electoral Roll.	10
15	Conveying the ECI's approval to DEOs.	2
	Total No. of Days	**161**